Question

Q1. Pingali Venkayya is widely credited for his significant contribution to the design of which national symbol of India?

पिंगली वेंकैया को भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक के डिज़ाइन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है?

SSC CGL 2025

(a) The National Emblem / राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह

(b) The National Anthem / राष्ट्रगान

(c) The National Flag / राष्ट्रीय ध्वज

(d) The National Flower / राष्ट्रीय पुष्प

Part I → Union (1-4)

Part II → Citizenship (5-11)

Solution

✅ **Correct Answer: (c) The National Flag / राष्ट्रीय ध्वज**

- **Pingali Venkayya (Jhanda Venkaiah) was the designer of the Indian National Flag (Tiranga).** / पिंगली वेंकय्या (झंडा वेंकय्या) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के निर्माता थे।
- **The flag was adopted by the Constituent Assembly on 22 July 1947.** / ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
- **The design has three horizontal stripes — Saffron (top), White (middle), and Green (bottom).** / ध्वज में तीन क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं — केसरिया (ऊपर), सफेद (बीच में), और हरा (नीचे)।
- **Ratio** – length : width – 3 : 2

Solution

- **The Ashoka Chakra with 24 spokes (navy blue) is placed in the centre on the white band.** / 24 तीलियों वाला अशोक चक्र (नेवी ब्लू) सफेद पट्टी के मध्य में स्थित होता है।
- **The Chakra was taken from the Lion Capital of Ashoka at Sarnath.** / यह चक्र सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है।
- **The flag symbolizes courage (saffron), peace and truth (white), and faith and fertility (green).** / ध्वज साहस (केसरिया), शांति और सत्य (सफेद), तथा आस्था और उर्वरता (हरा) का प्रतीक है।

Question

Q2. Which of the following words have been added to the Preamble by the 42nd Amendment?

निम्नलिखित में से कौन-से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे?

U.P.P.C.S. Mains 2010

I. Socialist / समाजवादी

II. Gram Swarajya / ग्राम स्वराज्य

III. Secular / पंथनिरपेक्ष

IV. Sovereign / प्रभुत्व संपन्न

(a) I, II, III

(b) I and III

(c) I, II, IV

(d) II, III, IV

Solution

✅ **Correct Answer: (b) I and III / I और III**

- **The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 added three new words to the Preamble: Socialist, Secular, and Integrity. / 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।**
- **The word "Sovereign" already existed from the original Constitution (1949). / "प्रभुत्व संपन्न" शब्द मूल संविधान (1949) में पहले से ही मौजूद था।**
- **The amendment was made during the Emergency period (Indira Gandhi's government). / यह संशोधन आपातकाल की अवधि (इंदिरा गांधी सरकार) के दौरान किया गया था।**
- **It is known as the "Mini Constitution" due to its vast changes. / व्यापक परिवर्तनों के कारण इसे "मिनी संविधान" कहा जाता है।**

Preamble of the Indian Constitution
भारतीय संविधान की प्रस्तावना

- Started with the words: “We, the People of India…” / इसकी शुरुआत “हम भारत के लोग…” शब्दों से होती है।
- Serves as the introduction to the Constitution of India. / यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना या परिचय के रूप में कार्य करती है।
- Declares India as a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic. / यह भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है।
- Aims to secure for all citizens / इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है:
  - Justice – social, economic, and political / न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
  - Liberty – of thought, expression, belief, faith, and worship / स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की

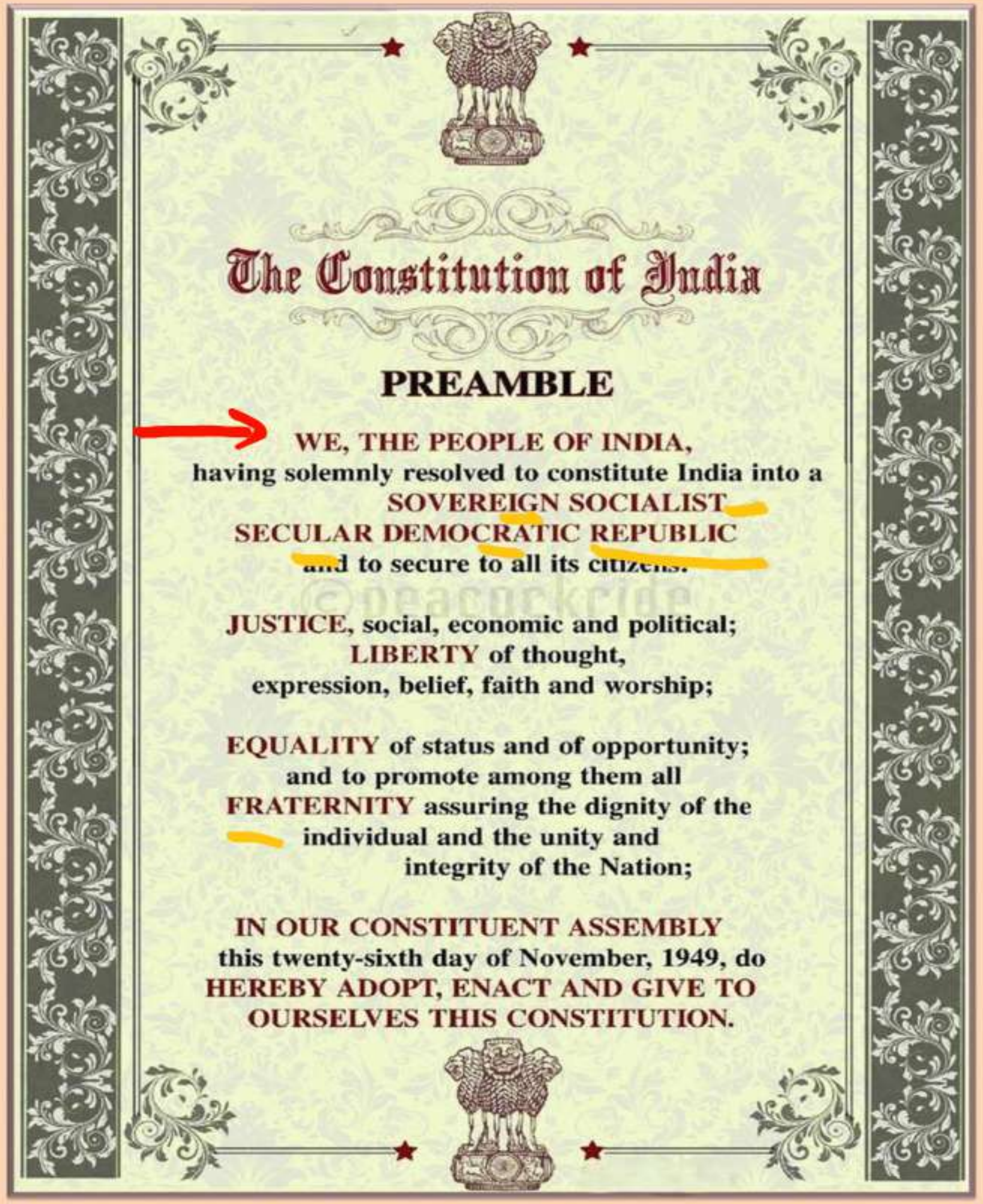

- ✓ Equality – of status and opportunity/ समानता – स्थिति और अवसर की
- ✓ Fraternity – assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation / बंधुता – व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना

- Amended once by the 42nd Amendment (1976) – added the words Socialist, Secular, and Integrity. / इसे एक बार 42वें संशोधन (1976) द्वारा संशोधित किया गया — जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।
- Based on the Objectives Resolution moved by Pandit Jawaharlal Nehru in 1946. / यह 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यों के प्रस्ताव पर आधारित है।

Question

Q3. Which of the following words does not appear before the word 'Republic' in the Preamble of the Constitution of India?

निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'Republic' शब्द से पहले नहीं आता है?

SSC CGL Tier-I – 19/04/2022 Shift-I

(a) Socialist / समाजवादी

(b) Sovereign / प्रभुत्व संपन्न

(c) Democratic / लोकतांत्रिक

(d) Federal / संघीय

Solution

✅ **Correct Answer: (d) Federal / संघीय**

- **The Preamble reads: "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic..."** / प्रस्तावना कहती है: "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक संकल्प करते हैं..."
- **The word 'Federal' does not appear in the Preamble.** / 'संघीय' (Federal) शब्द प्रस्तावना में नहीं है।
- **Although India has a federal structure, it is described as a "Union of States" (Article 1).** / यद्यपि भारत में संघीय ढांचा है, फिर भी इसे "राज्यों का संघ" (अनुच्छेद 1) कहा गया है।

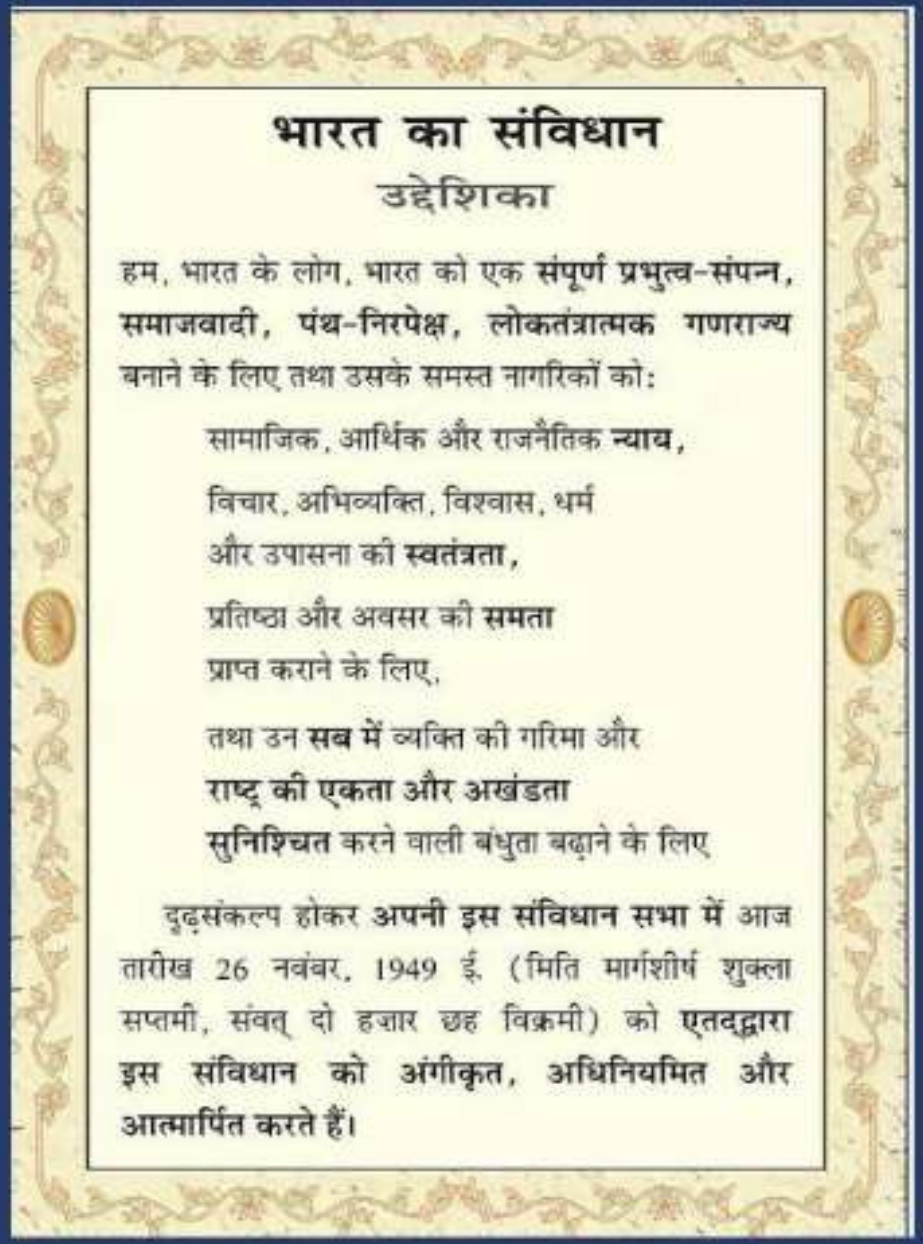

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

Question

Q4. Consider the following statements in regard to the Preamble of the Constitution and select the correct one using the code given below/ संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें:

U.P.P.C.S. Pre 2009

Statements / कथन:

1. The Objectives Resolution by Jawaharlal Nehru finally became the Preamble./ जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव अंततः उद्देशिका बना।
2. It is non-justiciable./ यह न्यायालय में लागू (न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय) नहीं है।
3. It can't be amended./ इसे संशोधित नहीं किया जा सकता।
4. Preamble cannot override specific provisions of the Constitution./ उद्देशिका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकती।

(a) Only 1 and 2 / केवल 1 और 2
(b) Only 1, 2 and 4 / केवल 1, 2 और 4
(c) Only 1, 2 and 3 / केवल 1, 2 और 3
(d) Only 2, 3 and 4 / केवल 2, 3 और 4

Solution

✅ Correct Answer: (b) Only 1, 2 and 4 / केवल 1, 2 और 4

- The Objectives Resolution (1946) moved by Jawaharlal Nehru became the basis of the Preamble. / जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्यों का प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना।
- The Preamble is non-justiciable, meaning it cannot be enforced in courts. / प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता।
- It can be amended (as per Kesavananda Bharati Case, 1973).
- / इसे संशोधित किया जा सकता है (केशवानंद भारती मामला, 1973 के अनुसार)।
- The Preamble cannot override the Constitution’s main provisions./ प्रस्तावना संविधान के मुख्य प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकती।
- It serves as the philosophical key of the Constitution. / यह संविधान की दार्शनिक कुंजी के रूप में कार्य करती है।

Question

Q5. Which unitary elements are found in the Indian Federal System?

भारतीय संघीय प्रणाली में कौन-से एकात्मक (unitary) तत्व पाए जाते हैं?

P.C.S. Pre 2017

i. Written Constitution / लिखित संविधान

ii. Rigid Constitution / कठोर संविधान

iii. Supremacy of the Constitution / संविधान की सर्वोच्चता

iv. Appointment of Governor / राज्यपाल की नियुक्ति

v. Decentralisation of Powers / शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

vi. President's approval on state bills / राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

vii. Constitutional Crisis / संवैधानिक संकट

viii. One Supreme Court / एक सर्वोच्च न्यायालय

(a) i, iii, vii
(b) ii, v, viii
(c) i, ii, v
(d) iv, vi, vii
(e) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Solution

✅ **Correct Answer: (d) iv, vi, vii**

- Unitary elements strengthen the central authority in the Indian federal system. / एकात्मक तत्व भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्रीय सत्ता को मजबूत करते हैं।
- Appointment of Governor by the Centre. / राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है।
- President's approval on State bills. / राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।
- Power during constitutional crisis or emergency. / संवैधानिक संकट या आपातकाल के दौरान केंद्र के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं।
- India is thus "Quasi-Federal" — federal in structure, unitary in spirit. / इसलिए भारत "अर्ध-संघीय" है — संरचना संघात्मक, भावना एकात्मक।
- Example: Article 356 allows Centre to take over State administration. / उदाहरण: अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्य का प्रशासन संभालने की अनुमति देता है।

Solution

Federal Features (संघात्मक विशेषताएँ)

- **Dual polity:** Division of powers between Union and States. / द्वैध शासन: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।
- **Written Constitution:** Clearly defines powers and responsibilities. / लिखित संविधान: शक्तियों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- **Division of powers:** Based on Union List, State List, and Concurrent List (Seventh Schedule). / शक्तियों का विभाजन: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) पर आधारित।
- **Supremacy of the Constitution:** Both Union and State governments work under it. / संविधान की सर्वोच्चता: केंद्र और राज्य सरकारें इसी के अधीन कार्य करती हैं।

Solution

- **Independent Judiciary:** Supreme Court acts as the guardian of the Constitution. / स्वतंत्र न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है।
- **Rigid Constitution:** Some provisions require special majority + states' consent. / कठोर संविधान: कुछ प्रावधानों में संशोधन हेतु विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति आवश्यक।
- **Bicameralism:** Lok Sabha and Rajya Sabha represent people and states. / द्विसदनीय प्रणाली: लोकसभा व राज्यसभा जनता व राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

Solution

Unitary Features (एकात्मक विशेषताएँ)

- Strong Centre: Union has more powers than states. / सशक्त केंद्र: केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ।
- Single Citizenship: Only one citizenship for all Indians. / एकल नागरिकता: सभी भारतीयों की केवल एक नागरिकता — भारतीय।
- Emergency Provisions: System becomes unitary during emergency. / आपातकालीन प्रावधान: आपातकाल में व्यवस्था एकात्मक हो जाती है।
- Single Constitution: One Constitution for entire India (earlier J&K was an exception). / एकल संविधान: पूरे भारत के लिए एक ही संविधान (पूर्व में J&K अपवाद)।

Solution

- Integrated Judiciary: No separate judiciary for states. / एकीकृत न्यायपालिका: राज्यों के लिए अलग न्याय प्रणाली नहीं।
- All-India Services: IAS, IPS create administrative unity. / अखिल भारतीय सेवाएँ: IAS, IPS आदि प्रशासनिक एकता स्थापित करते हैं।
- Appointment of Governors by the President. / राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- Unified Election Machinery: Election Commission conducts Centre + State elections. / एकीकृत निर्वाचन तंत्र: निर्वाचन आयोग केंद्र व राज्यों दोनों के चुनाव कराता है।

Question

Q6. Assertion (A): Indian federalism is called 'Quasi-federal'./ अभिकथन (A): भारतीय संघवाद को 'अर्ध-संघीय' कहा जाता है।

Reason (R): India has an independent judiciary with power of Judicial Review./ कारण (R): भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका है।

U.P.P.C.S. Pre 2020

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A). / (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही कारण है।

(b) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A). / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) का सही कारण नहीं है।

(c) (A) is true but (R) is false. / (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

(d) (A) is false but (R) is true. / (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

Solution

✅ **Correct Answer: (b) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).**

- **India is described as "Quasi-Federal" — meaning federal in form but unitary in spirit.** / भारत को "अर्ध-संघीय" कहा जाता है — अर्थात् रूप में संघात्मक, लेकिन भावना में एकात्मक।
- **The Centre has more powers than States (e.g., Emergency, Governor's appointment).** / केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं (जैसे आपातकाल, राज्यपाल की नियुक्ति)।
- **Judicial Review ensures balance but is not the reason for quasi-federalism.** / न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) संतुलन बनाए रखता है, लेकिन अर्ध-संघीय संरचना का कारण नहीं है।
- **Term "Quasi-Federal" was given by K.C. Wheare.** / "Quasi-Federal" शब्द के.सी. व्हेयर द्वारा दिया गया था।
- **Dr. B.R. Ambedkar described India as "a federation with a strong Centre."** / डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने भारत को "सशक्त केंद्र वाला संघ" कहा था।

Question

Q7. With reference to the federal system in India, which of the following statements is/are correct?/ भारत की संघीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं?

Statements / कथन:

1. States have no right to secede from the Union under the Constitution of India./ भारतीय संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
2. Just advocacy of secession will have the protection of freedom of expression./ केवल अलगाव की वकालत करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत आता है।

U.P.P.C.S. Pre 2019

(a) 1 only / केवल 1
(b) 2 only / केवल 2
(c) Both 1 and 2 / दोनों 1 और 2
(d) Neither 1 nor 2 / न तो 1 और न ही 2

Solution

✅ Correct Answer: (a) 1 only / केवल 1

- India is described as a "Union of States" (Article 1), meaning no state can secede from the Union. / भारत को "राज्यों का संघ" (अनुच्छेद 1) कहा गया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता।
- Advocacy of secession or disintegration is not protected under freedom of expression (Article 19(1)(a)). / अलगाव या विघटन की वकालत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) के तहत संरक्षित नहीं है।
- The Indian federal system ensures unity and integrity of the nation. / भारतीय संघीय व्यवस्था राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है।
- Federalism in India = Indestructible Union of Destructible States. / भारत में संघवाद = नष्ट हो सकने वाले राज्यों का अविनाशी संघ।

Solution

1-4

Article 1 – Name and Territory of the Union
अनुच्छेद 1 – संघ का नाम और क्षेत्र

- India is known as "Bharat". / भारत को "भारत" के नाम से जाना जाता है।
- It shall be a Union of States (not a federation). / यह राज्यों का संघ होगा (संघात्मक राज्य नहीं)।
- Indicates unity and indestructibility of the nation. / यह राष्ट्र की एकता और अविनाशी स्वरूप को दर्शाता है।
- Term Union of States implies that states cannot secede from India. / "राज्यों का संघ" शब्द दर्शाता है कि राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते।

Solution

Article 2 – Admission or Establishment of New States / अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

- **Parliament has power to admit new states into the Union. / संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार है।**
- **Can establish new states on terms and conditions it thinks fit. / संसद उपयुक्त समझे जाने वाले नियमों व शर्तों पर नए राज्य स्थापित कर सकती है।**
- **Example: Sikkim admitted as 22nd state in 1975. / उदाहरण: सिक्किम को 1975 में 22वां राज्य बनाया गया था।**

Question

Q8. Which Article defines State and Union Territories for the purposes of the Constitution?

संविधान के उद्देश्यों के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन-सा है?

SSC CGL 2025

(a) Article 1 / अनुच्छेद 1

(b) Article 3 / अनुच्छेद 3

(c) Article 239 / अनुच्छेद 239

(d) Article 240 / अनुच्छेद 240

Solution

✅ Correct Answer: (a) Article 1 / अनुच्छेद 1

- **Article 1: "India, that is Bharat, shall be a Union of States."** / अनुच्छेद 1: "भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा।"
- **It defines India as a Union of States and Union Territories.** / यह भारत को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संघ के रूप में परिभाषित करता है।
- **The term "Union" emphasizes that States have no right to secede.** / "संघ" शब्द इस बात पर जोर देता है कि राज्य अलग होने का अधिकार नहीं रखते।
- **Part I of the Constitution (Articles 1–4) deals with the Union and its territories.** / संविधान का भाग I (अनुच्छेद 1–4) संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है।

Solution

Article 3 – Formation of New States and Alteration of Areas, Boundaries, or Names / अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का गठन एवं क्षेत्र, सीमाएँ या नाम बदलना

Parliament can/ संसद कर सकती है:

- Form new states by separation or uniting territories. / क्षेत्रों को अलग या मिलाकर नए राज्य बना सकती है।
- Alter boundaries or rename any state. / किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है या उसका नाम परिवर्तित कर सकती है।
- Requires President's recommendation and consultation with the concerned State Legislature (not binding). / इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश और सम्बंधित राज्य विधानमंडल से परामर्श आवश्यक है (लेकिन इसे मानना बाध्यकारी नहीं)।
- Example: Bifurcation of Andhra Pradesh (creation of Telangana, 2014). / आंध्र प्रदेश का विभाजन (तेलंगाना का गठन, 2014)।

Solution

Article 4 – Laws made under Articles 2 & 3
अनुच्छेद 4 – अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून

- Any law made under Articles 2 or 3 is not considered a Constitutional Amendment. / अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता।
- Such laws can change First and Fourth Schedules (State names, boundaries, and Rajya Sabha seats). / ऐसे कानून प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों (राज्यों के नाम, सीमाएँ और राज्यसभा सीटें) में परिवर्तन कर सकते हैं।

Question

Q9. Whose death led to the creation of the first linguistic state of India, Andhra Pradesh?

भारत के प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश के गठन का कारण किसकी मृत्यु थी?

SSC Phase XIII – 29/07/2025 Shift-I

1953 founded
1956 linguistic basic

(a) Potti Sriramulu / पोट्टी श्रीरामलू
(b) Pingali Venkayya / पिंगली वेंकैया
(c) R.K. Shanmugam Chetty / आर.के. शन्मुखम चेट्टी
(d) Jagjivan Ram / जगजीवन राम

Solution

✅ Correct Answer: (a) Potti Sriramulu / पोट्टी श्रीरामलू

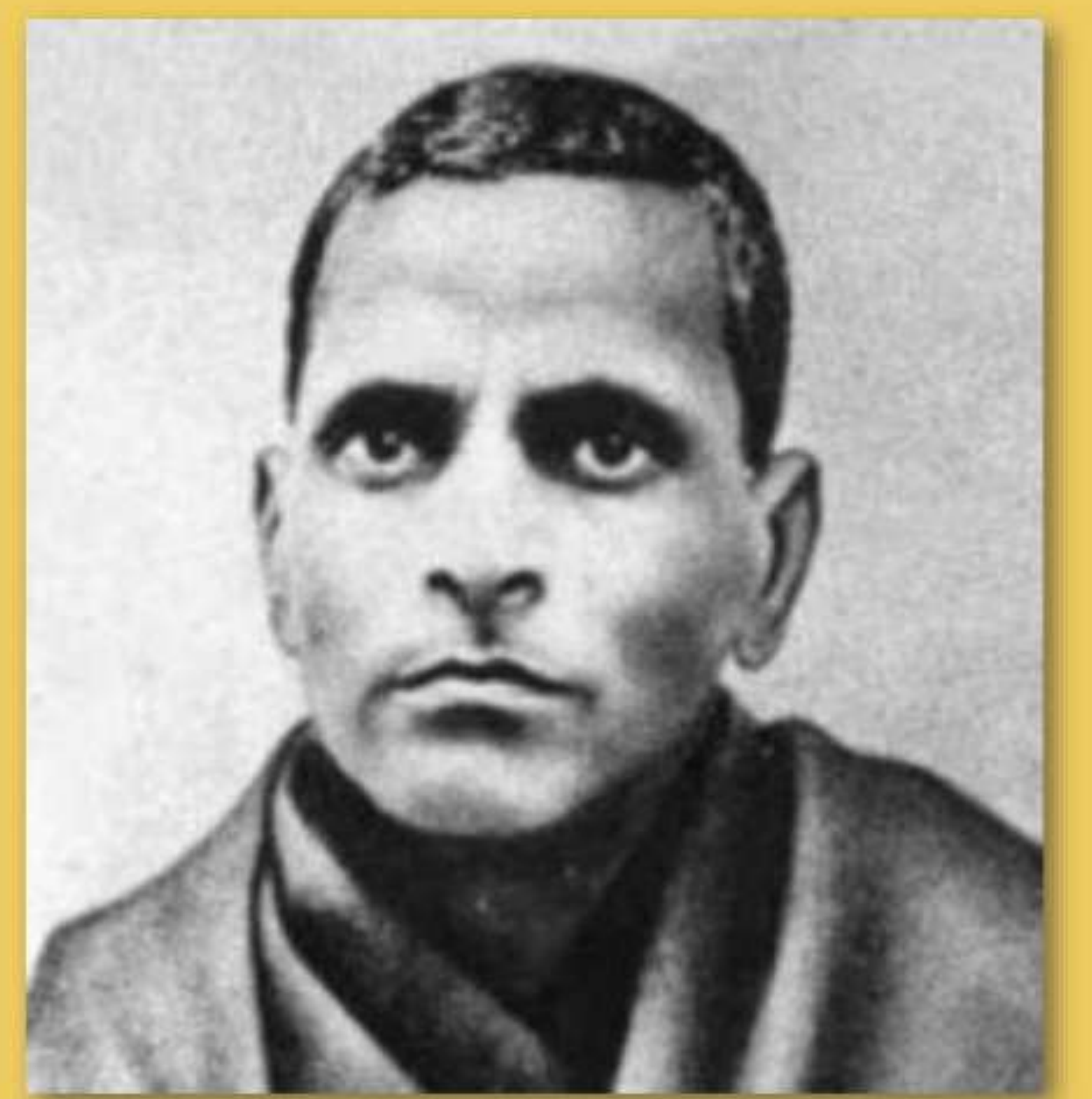

- Potti Sriramulu fasted unto death in 1952, demanding a separate Telugu-speaking state. / पोट्टी श्रीरामलू ने 1952 में एक अलग तेलुगु-भाषी राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन किया।
- His death led to mass protests, resulting in the formation of Andhra Pradesh in 1953. / उनकी मृत्यु के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनके परिणामस्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ।
- It became India's first linguistic state. / यह भारत का पहला भाषाई राज्य बना।
- Later, the States Reorganisation Act (1956) created states on linguistic basis. / बाद में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) के तहत राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया।

Solution

State	Date / Year of Formation
Andhra State	1953
Maharashtra	1960
Gujarat	1960
Haryana	1966
Punjab (reorganised)	1966
Meghalaya	1972
Manipur	1972
Tripura	1972
Sikkim	1975
Chhattisgarh	2000
Uttarakhand (Uttaranchal)	2000
Jharkhand	2000
Telangana	2014

Bombay

Question

Q10. One of the following statements is incorrect. Point out/ निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। उसे चिन्हित करें:

R.A.S./R.T.S. Pre 2016

(a) The State of Mysore was renamed as Tamil Nadu. / मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया।

(b) Goa was separated from Daman and Diu. / गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया।

(c) The State of Bombay was split into Gujarat and Maharashtra. / बॉम्बे राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया।

(d) Himachal Pradesh was previously in the list of Union Territories. / हिमाचल प्रदेश पहले केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में था।

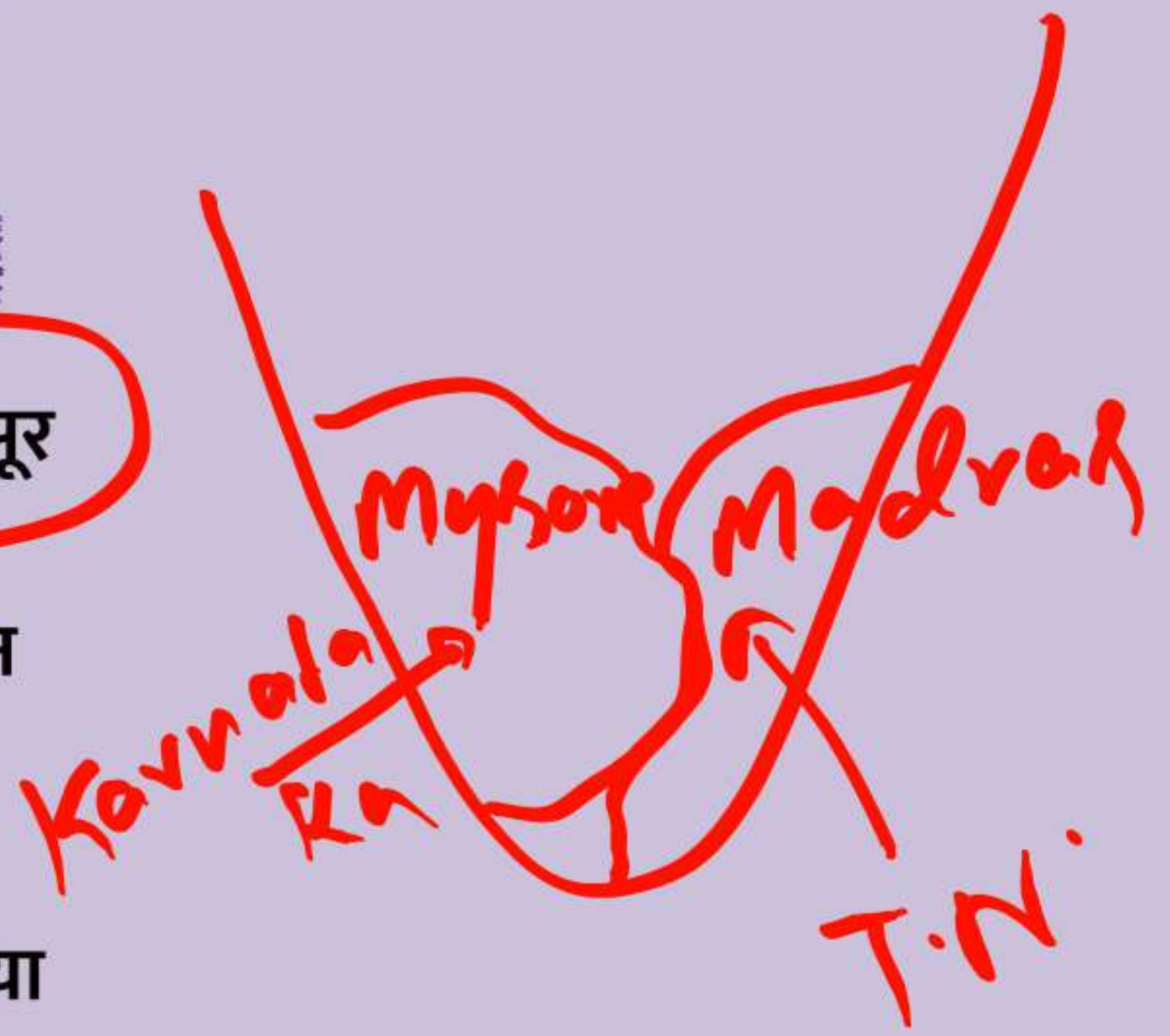

Solution

✅ **Correct Answer: (a) The State of Mysore was renamed as Tamil Nadu. / मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया।**

- The State of Mysore was renamed as Karnataka (1973). / मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया (1973)।
- Madras State was renamed as Tamil Nadu (1969). / मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया (1969)।
- Goa, Daman and Diu were separated in 1987. / गोवा, दमन और दीव को 1987 में अलग कर दिया गया।
- Bombay was divided into Maharashtra & Gujarat (1960). / बॉम्बे को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया।
- Himachal Pradesh was a Union Territory (1950) before becoming a state in 1971. / हिमाचल प्रदेश 1950 में एक केंद्रशासित प्रदेश था, जो 1971 में राज्य बना।

Question

Q11. Who among the following is not eligible for registering as an Overseas Citizen of India (OCI) cardholder under the Citizenship Amendment Act, 2015?/ निम्नलिखित में से कौन 2015 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI) कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है?

U.P.P.C.S. Mains 2016

(a) A minor child whose parents are an Indian citizen. / एक नाबालिग बच्चा जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं।

(b) Spouse of foreign origin of an Indian citizen. / एक विदेशी मूल का जीवनसाथी जो भारतीय नागरिक से विवाहित है।

(c) Indian who migrated to Pakistan after partition. / वह भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया।

(d) A great-grandchild of a person whose grandparents were Indian citizens at the commencement of the Constitution. / ऐसा परनाती या परपोता जिसके दादा-दादी संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे।

Bangladesh

Solution

✅ **Correct Answer: (c) Indian who migrated to Pakistan after partition. / वह भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया।**

- **Under the Citizenship (Amendment) Act, 2015, persons of Indian origin (except those from Pakistan or Bangladesh) can register as Overseas Citizens of India (OCI).** / नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर) भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI) के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं।
- **A person who migrated to Pakistan after partition is not eligible.** / विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को पात्र नहीं माना जाता।
- **OCI provides multiple-entry, multipurpose lifelong visa for visiting India.** / OCI भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीज़ा प्रदान करता है।
- **It does not grant political rights (like voting).** / यह राजनीतिक अधिकार (जैसे मतदान का अधिकार) प्रदान नहीं करता है।

Question

1955

Q12. In which year was the Citizenship Act passed in India?

भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?

SSC GD 29/11/2021 Shift-II,
SSC CHSL 17/03/2023 Shift-III

(a) 1951
(b) 1955
(c) 1959
(d) 1964

Solution

✅ **Correct Answer: (b) 1955**

- **The Citizenship Act, 1955 lays down the rules and procedures for acquiring and losing Indian citizenship. / नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और खोने के नियम तथा प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।**
- **It provides for citizenship by birth, descent, registration, naturalisation, and incorporation of territory. / यह जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण तथा क्षेत्र के विलय द्वारा नागरिकता प्रदान करता है।**
- **The Act has been amended six times / इस अधिनियम में छह बार संशोधन हुआ है — 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019।**
- **Ministry of Home Affairs administers citizenship provisions. / गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी प्रावधानों का संचालन करता है।**

Citizenship in India –The Citizenship Act, 1955

Mode of Acquisition/ नागरिकता प्राप्त करने का तरीका	Key Provisions (as per NCERT & Act) मुख्य प्रावधान (NCERT व अधिनियम अनुसार)	Examples / Notes / उदाहरण / टिप्पणियाँ
1. By Birth **जन्म से**	A person born in India is a citizen:**भारत में जन्मा व्यक्ति नागरिक होता है:–** • **Before 1 July 1987 → Citizen irrespective of parents' nationality. / 1 जुलाई 1987 से पहले → माता-पिता की नागरिकता के बिना नागरिकता मिलती है।** • **Between 1 July 1987 – 2 Dec 2004 → Citizen if either parent is Indian./ 1 जुलाई 1987 – 2 दिसंबर 2004 → यदि किसी एक अभिभावक भारतीय हो।** • **After 3 Dec 2004 → Citizen if one parent is Indian & other not illegal migrant./ 3 दिसंबर 2004 के बाद → एक अभिभावक भारतीय और दूसरा illegal migrant न हो।**	Based on *jus soli* (principle of birth). **जन्म आधारित सिद्धांत पर आधारित।**
2. By Descent **वंश से**	A person born outside India is a citizen if:**भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी यदि:** • **Before 10 Dec 1992 → Father was Indian./ 10 दिसंबर 1992 से पहले → पिता भारतीय हों।** • **After 10 Dec 1992 → Either parent Indian./ 10 दिसंबर 1992 के बाद → माता-पिता में से कोई भी भारतीय हो।** • **Birth must be registered at Indian mission/consulate. / जन्म को भारतीय दूतावास में पंजीकृत करना आवश्यक है।**	Example: Child born to Indian parents in the UK. **उदाहरण: यूके में भारतीय माता-पिता से जन्मा बच्चा।**

Mode of Acquisitionनागरिकता प्राप्त करने का तरीका	Key Provisions (as per NCERT & Act) मुख्य प्रावधान (NCERT व अधिनियम अनुसार)	Examples / Notesउदाहरण / टिप्पणियाँ
3. By Registration पंजीकरण द्वारा	• **Certain persons of Indian origin or spouses/minors of Indian citizens can apply./ भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिकों के spouse/नाबालिग आवेदन कर सकते हैं।** • **Must ordinarily reside in India for 7 years. / आवेदन से पूर्व 7 वर्ष भारत में निवास आवश्यक।**	Example: NRI returning permanently. **उदाहरण: स्थायी रूप से बसने वाला NRI।**

4. By Naturalisation
प्राकृतिककरण द्वारा
	• Foreigners can acquire citizenship if: / **विदेशी नागरिक नागरिकता पा सकते हैं यदि:–**
	  • **Resided in India for 12 years (in last 14 years). / पिछले 14 वर्षों में 12 वर्ष भारत में रहे हों।**
	  • **Fulfil Third Schedule qualifications./ तीसरी अनुसूची की शर्तें पूरी हों।**
		Example: A long-term foreign resident granted citizenship.
		उदाहरण: लंबे समय से भारत में रह रहा विदेशी।

5. By Incorporation of Territory क्षेत्र के विलय द्वारा	**When new territory joins India, Govt of India decides citizenship. / जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है, तब भारत सरकार तय करती है कि कौन नागरिक बनेगा।**	Example: Sikkim (1975), Goa (1961). **उदाहरण: सिक्किम (1975), गोवा (1961)**

Question

Q13. Which of the following Articles of the Indian Constitution deals with citizenship?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है?

SSC CGL Tier-I – 14/07/2023 Shift-I

(a) Articles 5 to 11 / अनुच्छेद 5 से 11
(b) Article 2 to 4 / अनुच्छेद 2 से 4
(c) Articles 25 to 31 / अनुच्छेद 25 से 31
(d) Articles 15 to 21 / अनुच्छेद 15 से 21

Part II

25-28 Religion

14-18 → Equality

Solution

✅ **Correct Answer: (a) Articles 5 to 11 / अनुच्छेद 5 से 11**

- **Part II (Articles 5–11) of the Constitution deals with Citizenship.** / संविधान का भाग II (अनुच्छेद 5–11) नागरिकता से संबंधित है।
- **It defines citizenship at the commencement of the Constitution (1950).** / यह संविधान के प्रारंभ (1950) के समय की नागरिकता को परिभाषित करता है।

Solution

Key provisions / प्रमुख प्रावधान:

- **Article 5: Citizenship by domicile/** निवास (डोमिसाइल) के आधार पर नागरिकता
- **Article 6: Rights of migrants from Pakistan** / पाकिस्तान से आए प्रवासियों के अधिकार
- **Article 7: Rights of migrants to Pakistan** / पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों के अधिकार
- **Article 8: Persons of Indian origin residing abroad** / विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार
- **Article 10 & 11: Parliament's power to regulate citizenship by law** / नागरिकता संबंधी कानून बनाने व विनियमित करने की संसद की शक्ति

Question

Q14. Indian Citizenship is granted by ______.

भारतीय नागरिकता ______ द्वारा प्रदान की जाती है।

SSC CGL Tier-I – 04/09/2016, 1:15 PM

(a) The President of India / भारत के राष्ट्रपति

(b) The Prime Minister / प्रधानमंत्री

(c) The Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय

(d) The Ministry of External Affairs / विदेश मंत्रालय

Solution

✅ **Correct Answer: (c) The Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय**

- **The Ministry of Home Affairs (MHA) is responsible for granting Indian citizenship under the Citizenship Act, 1955. / नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय (MHA) की होती है।**

- **Applications are processed by State Governments and then forwarded to the Central Government. / आवेदन पहले राज्य सरकारों द्वारा जांचे जाते हैं और फिर केंद्र सरकार को भेजे जाते हैं।**

- **The President only approves or notifies, but the execution authority lies with the MHA. / राष्ट्रपति केवल अनुमोदन या अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यान्वयन का अधिकार गृह मंत्रालय के पास होता है।**

- **Citizenship divisions handle registration, renunciation, and naturalisation cases. / नागरिकता प्रभाग पंजीकरण, त्याग (renunciation) और प्राकृतिककरण (naturalisation) से जुड़े मामलों को संभालते हैं।**

Question

Q15. Consider the following statements:

1. Article 131A gave High Courts exclusive power to decide on central laws' validity./ अनुच्छेद 131A ने उच्च न्यायालयों को केंद्रीय कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने की विशिष्ट शक्ति दी थी।

2. It was repealed by the 43rd Constitutional Amendment./ इसे 43वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

SSC CGL 2025

(a) Only 1 / केवल 1

(b) Only 2 / केवल 2

(c) Both 1 and 2 / दोनों 1 और 2

(d) Neither 1 nor 2 / न तो 1 और न ही 2

Solution

✅ Correct Answer: (b) Only 2 / केवल 2

- Article 131A (inserted by the 42nd Amendment, 1976) gave exclusive jurisdiction to the Supreme Court (not High Courts) to determine the constitutional validity of Central laws. / अनुच्छेद 131A (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) ने केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता तय करने का विशेष अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को दिया था, उच्च न्यायालयों को नहीं।

- It was repealed by the 43rd Amendment Act, 1977 to restore High Courts' jurisdiction. / 43वें संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, जिससे उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र बहाल हुआ।

- The 42nd Amendment had centralized many powers, later corrected by the 43rd Amendment after the Emergency. / 42वें संशोधन ने अनेक शक्तियों को केंद्रित कर दिया था, जिन्हें आपातकाल के बाद 43वें संशोधन द्वारा संतुलित किया गया।

Question

Q16. Consider the following statements:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. Article 263 empowers Parliament to establish the Inter-State Council./ अनुच्छेद 263 संसद को अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है।
2. The Council can investigate inter-state disputes./ यह परिषद अंतर-राज्यीय विवादों की जांच कर सकती है।
3. Its composition includes the PM and Union Ministers./ इसकी संरचना में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।

(a) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(b) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(c) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(d) 1, 2 and 3 / सभी 1, 2 और 3

SSC CGL 2025

SelectionWay

Solution

✅ Correct Answer: (a) 2 and 3 only / केवल 2 और 3

- Article 263 authorizes the President (not Parliament) to establish an Inter-State Council (ISC). / अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति (संसद नहीं) को अंतर-राज्य परिषद (ISC) स्थापित करने का अधिकार देता है।

- It aims to promote coordination between Centre and States. / इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है।

- The Inter-State Council can / अंतर-राज्य परिषद यह कर सकती है:
  - ✓ Investigate and discuss inter-state disputes. / राज्यों के बीच विवादों की जांच और चर्चा।
  - ✓ Offer recommendations for better coordination. / बेहतर समन्वय हेतु सुझाव देना।

Solution

- Composition: PM (Chairman), Union Ministers, and Chief Ministers of all States and UTs with legislatures. / संरचना: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय मंत्री, तथा सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री।

- Established in 1990 under the recommendation of the Sarkaria Commission. / इसे 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया।

Question

SSC CGL 2025

Q17. Which of the following statements correctly applies the weighted voting mechanism under Article 279A(9) of the Indian Constitution?/ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(9) के तहत भारित मतदान तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) The Centre holds 75% of the voting power in the GST Council. / केंद्र के पास GST परिषद में 75% मतदान शक्ति होती है।

(b) A GST Council decision can be passed solely with the support of the Centre and one State. / GST परिषद का निर्णय केवल केंद्र और एक राज्य के समर्थन से पारित किया जा सकता है।

(c) The States collectively have twice the voting weight of the Centre in the GST Council. / राज्यों के पास GST परिषद में केंद्र की तुलना में दोगुना मतदान भार होता है।

(d) Each State has equal weightage as the Centre in GST Council voting. / प्रत्येक राज्य का मतदान भार केंद्र के बराबर होता है।

Solution

✅ Correct Answer: (c) The States collectively have twice the voting weight of the Centre in the GST Council. / राज्यों के पास केंद्र की तुलना में दोगुना मतदान भार होता है।

Article 279A(9) provides the voting mechanism in the GST Council. / अनुच्छेद 279A(9) GST परिषद में मतदान की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

Total votes are weighted as / कुल मतों का भार निम्न प्रकार होता है:

- **Centre → 1/3rd (33.33%) of total votes.**
- **All States collectively → 2/3rd (66.67%) of total votes.**
- **A decision requires at least 75% of weighted votes to pass. / किसी भी निर्णय के लिए कम से कम 75% भारित मतों की आवश्यकता होती है।**
- **Ensures cooperative federalism by balancing Centre–State interests. / केंद्र–राज्य हितों को संतुलित कर सहकारी संघवाद सुनिश्चित करता है।**

A 75%

GST Council
33
1/3 11 Member
2/3 22 Member

Article 279A – Goods and Services Tax (GST) Council
अनुच्छेद 279A – वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद

- Added by the 101st Constitutional Amendment Act, 2016. / 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया।

- Provides for the constitution of the GST Council. / GST परिषद के गठन का प्रावधान करता है।

- Chairperson: Union Finance Minister. / अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।

- Members / सदस्य:
  - ✓ Union Minister of State for Finance or Revenue. / वित्त या राजस्व राज्य मंत्री।
  - ✓ Finance Ministers (or equivalents) of all States and UTs with legislature. / सभी राज्यों व विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री (या समकक्ष अधिकारी)।
  - ✓ Chairperson of the Council: Union Finance Minister. / परिषद के अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।

Question

Q18. Which of the following correctly reflects the legal implication of Article 255 regarding presidential or governor's assent to bills?
निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद 255 के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित विधायी प्रभाव को सही रूप से दर्शाता है?

SSC CGL 2025

(a) State law is void without written Governor assent. / राज्य कानून राज्यपाल की लिखित स्वीकृति के बिना अमान्य होता है।
(b) Mention of assent is mandatory for validity. / वैधता के लिए स्वीकृति का उल्लेख अनिवार्य है।
(c) Omission of prior recommendation doesn't invalidate law if assent is given. / यदि स्वीकृति दी गई है तो पूर्व अनुशंसा का अभाव कानून को अमान्य नहीं बनाता।
(d) President's assent must precede legislative passage to be valid. / वैधता के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति विधेयक पारित होने से पहले आवश्यक है।

Solution

✅ **Correct Answer: (c) Omission of prior recommendation doesn't invalidate law if assent is given. / यदि स्वीकृति दी गई है तो पूर्व अनुशंसा का अभाव कानून को अमान्य नहीं बनाता।**

- **Article 255 states that the absence of prior recommendation or sanction does not invalidate a law if the President or Governor later gives assent.** / अनुच्छेद 255 कहता है कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल बाद में अनुमति दे दें, तो पूर्व अनुशंसा या स्वीकृति न होने पर भी कोई विधेयक अमान्य नहीं होता।
- **It ensures procedural lapses don't nullify legislative acts.** / यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण विधायी कार्य निरस्त न हों।
- **Provides flexibility to legislative processes in both Union and State laws.** / यह केंद्र और राज्य दोनों के विधायी प्रक्रियाओं में लचीलापन प्रदान करता है।
- **Thus, once assent is given, the law becomes valid and enforceable.** / इसलिए, एक बार अनुमति (assent) मिल जाने पर कानून वैध और लागू करने योग्य हो जाता है।

Question

Q19. As per Article 279A of the Indian Constitution, the GST Council's decisions require what kind of majority of the weighted votes of the members present and voting?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार, GST परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है?

SSC CGL 2025

(a) Simple majority / साधारण बहुमत

(b) Three-fourths majority / तीन-चौथाई बहुमत — 75%

(c) Two-thirds majority / दो-तिहाई बहुमत

(d) Half majority / आधा बहुमत

Solution

✅ Correct Answer: (b) Three-fourths majority

- Under Article 279A(9), a decision in the GST Council is passed by a three-fourths majority of weighted votes. / अनुच्छेद 279A(9) के अनुसार, GST परिषद में कोई निर्णय भारित मतों के तीन-चौथाई बहुमत से पारित होता है।
- Centre → 1/3rd weight, States → 2/3rd weight collectively. / केंद्र → 1/3 भार, राज्य सामूहिक रूप से → 2/3 भार।
- Ensures that no single entity (Centre or State) can dominate. / यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पक्ष (केंद्र या राज्य) प्रभुत्व स्थापित न कर सके।
- Promotes cooperative federalism and joint decision-making on GST matters. / यह सहकारी संघवाद और GST से जुड़े मामलों में संयुक्त निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देता है।

Question

Q20. Assertion (A): The Bharatiya Sakshya Adhiniyam recognizes electronic records as primary evidence./ अभिकथन (A): भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है।

Reason (R): Section 62 states that electronic records are secondary unless accompanied by a printed certificate./ कारण (R): धारा 62 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तब तक द्वितीयक होते हैं जब तक कि वे मुद्रित प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत न किए जाएं।

SSC CGL 2025

(a) Both A and R are true, and R is the correct of A. / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) का सही कारण है।

(b) Both A and R are true, but R is not the correct of A. / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) का सही कारण नहीं है।

(c) A is true, R is false. / (A) सत्य है, (R) असत्य है।

(d) A is false, R is true. / (A) असत्य है, (R) सत्य है।

Solution

✅ Correct Answer: (c) : (A) सत्य है, (R) असत्य है।

- The Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023 replaced the old Indian Evidence Act, 1872. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 ने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित किया।
- It recognizes electronic records (emails, documents, photos, videos) as primary evidence under Section 61–62. / यह धारा 61–62 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (ईमेल, दस्तावेज़, फोटो, वीडियो) को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है।
- Section 62 does not declare them secondary evidence; rather, it equates electronic records with original documents. / धारा 62 इन्हें द्वितीयक साक्ष्य नहीं मानती, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मूल दस्तावेज़ के समान दर्जा देती है।
- This modernization aligns Indian law with digital evidence standards./ यह आधुनिकीकरण भारतीय विधि को डिजिटल साक्ष्य मानकों के अनुरूप बनाता है।

THANK YOU